





"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"-वेडेल फिलिपा

# दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 31 मार्च 2024 रविवार

## सम्पादकीय

### सत्ता के समीकरण

चर्चित कहावत रही है कि प्रेम व युद्ध में सब कुछ जायज मान लिया जाता है। अब इसमें राजनीति को भी शामिल मान लिया गया है। सत्ता के समीकरणों के लिये राजनीति की मुख्यधारा में शामिल होने के बाद शुचिता का प्रमाणण हो ही जाता है। फिर एक विज्ञापन की तर्ज पर कहा जाता है कि ये दाग अच्छे हैं। ये स्थिति हाल-फिलहाल ही नहीं, देश के राजनीतिक परिदृश्य में दशकों से जारी रही है। राजनीतिक सुविधा के हिसाब से गुण-दोषों की व्याख्या की जाती रही है। कहावत भी है-समर्थ को नहीं दोष गुसाईं। जैसे सबल व्यक्ति को दोषों को भी गुणों की तरह दर्शाया जाता है, वैसे ही राजनीति की मुख्यधारा में भी अवगुणों को गुण रूप में दर्शाया का विमर्श तक की हकीकत है। हाल फिलहाल के दौर में कई राजनेताओं के हृदय परिवर्तन और दल बदलने पर शुचिता के जुमले आम हैं। विपक्षी दल ऐसा ही कुछ सत्ताकूट गठबंधन में शामिल होने के आठ माह बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल से जुड़े एक मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट लगने के बाद कह रहे हैं। उनके अक्सर आरोप होते हैं कि राजनीतिक भयादोहन के लिये सरकारी एजेंसियों का उपयोग किया जाता रहा है। दरअसल, प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइन्स विलय मामले में विसंगतियों के खिलाफ सीबीआई ने रिपोर्ट दर्ज की थी। उल्लेखनीय है कि अजित पवार वाला एनसीपी घटक कुछ माह पूर्व राइज में शामिल हो गया था। दरअसल, एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइन्स विलय के समय प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के पद पर थे। उसी दौरान एक मामले में उनके क्रियाकलापों को संदिग्ध बताया गया था। तब इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने भी उनसे पूछताछ की थी। उन पर मुनाफे वाले रूट्स के जरिये अपने एक मित्र को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा था। उल्लेखनीय है कि दिल्ली की एक अदालत एक मामले में क्लोजर रिपोर्ट पर अगले माह के मध्य में विचार करेगी।

वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में 'माइनिंग किंग' के नाम से चर्चित जनार्दन रेड्डी की भाजपा में वापसी भी चर्चाओं में है। कहा जा रहा है कि यह प्रसंग राजग के 'अबकी बार,बार सौ पार' की मुहिम का हिस्सा है। रेड्डी का इतिहास खासा विवादों में रहा है और उन्हें खनन की बुनियाद का बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है। उनका नाम एक दूध के अयस्क कदाचार मामले में जोड़ा जाता रहा है। इसके अलावा कई अन्य मामलों के चलते भाजपा ने कालांतर उनसे दूरी बना ली थी। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कल्याण राज्य प्रगति पक्ष पार्टी बनाकर वे खुद भी विधानसभा पहुंचे थे और उनके भाई व अन्य पारिवारिक सदस्यों ने अच्छे-खासे धन अर्जित इलाके में हासिल किये थे। आज जबकि राज्य में कांग्रेस सत्ता में है तो भाजपा ने जनाधार बढ़ाने के लिये रेड्डी की पार्टी में वापसी की राह सुनिश्चित की है। हालांकि, एक समय रेड्डी से बात करने से भी पार्टी के बड़े नेता कतराते थे, अब वे ही माइन्स किंग की वापसी को सुखद बता रहे हैं। उनकी अपनी-अपनी दलीलें हैं। यहां तक कि रेड्डी की पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात हुई है। इस पर जनार्दन रेड्डी की दलील है कि उनका तो पार्टी में ही जन्म हुआ है, यह तो घर वापसी हुई है। राजनीतिक पंडित बता रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में न केवल जनार्दन रेड्डी विधानसभा के लिये चुने गए थे बल्कि बेल्लारी विधानसभा सीट से भी उनकी पत्नी को एकमुश्त वोट मिले थे। इसके अलावा उनकी पार्टी के कई नेताओं को भी ठीक-ठाक वोट मिले थे। जाहिर है रेड्डी के पार्टी से बाहर रहने को भाजपा अपने वोट बैंक में बिखराने के तौर पर देख रही थी। दरअसल, जनार्दन रेड्डी बेल्लारी, कोपल व रायचूर लोकसभा क्षेत्रों में खासा प्रभाव रखते हैं। यही वजह है कि दामां को नजरअंदाज करते हुए उनकी वापसी हुई है। वैसे जनार्दन रेड्डी अभी बेल्लारी से चुनाव लड़ने वाली सुष्मा स्वराज के करीबी लोगों के रूप में जाने जाते हैं। वहीं यदियुष्मा सरकार बनाने के दौर में आप्रेशन लोटस में उनकी बड़ी भूमिका बतानी जाती रही है।

# लोकसभा चुनाव और केजरीवाल की गिरफ्तारी

## -उमेश चतुर्वेदी-

शराब घोटाले में केजरीवाल के पहले उनके दो स्तंभों पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी जमानत की याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। इसी शराब नीति घोटाले में दिल्ली से तीसरी बड़ी गिरफ्तारी केजरीवाल की हुई है। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी हो, इसी बीच किसी राज्य के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो और उस पर राजनीति ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी का दावा है कि इन गिरफ्तारियों के पीछे कांग्रेस राजनीति नहीं है। लेकिन राजनीति और लोक का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जो इन गिरफ्तारियों के पीछे राजनीति देख रहा है। मोदी विरोधी आर्द्रुणीडाईए गठबंधन में चूकि केजरीवाल भी शामिल है, लिहाजा गठबंधन के नेता इन गिरफ्तारियों को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बताने-बनाने में उद्वेग हैं। उनका एक ही सवाल है कि आखिर सिर्फ विपक्षी नेताओं को ही ईडी या सीबीआई निशाना क्यों बना रहा है? बार-बार ऐसा कहकर एक तरह से मोदी विरोधी मोर्चे के नेताओं की कोशिश यह है कि इन गिरफ्तारियों को भ्रष्टाचार की बजाय सिर्फ राजनीति का रंग दिया जाए और इससे जरिए मोदी विरोधी जोरों की फसल काट ली जाय।

लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा संभव है? मोदी के उभार के बाद के दोनों संसदीय चुनावों में दिल्ली विधानसभा में अपार बहुमत रखने वाली आम आदमी पार्टी एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई है। इस बार तो आम आदमी पार्टी ने इन कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है, जिसके भ्रष्टाचार के विरोध



में उसका समूचा अनुत्पल पनपता रहा। दिल्ली में लोकसभा की सात सीटें हैं, जिनमें तीन सीटों पर जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वहीं आम आदमी पार्टी चार सीटों पर मैदान में है। मोदी घोटाले आम चुनावों में आम आदमी पार्टी की स्थिति तीसरे नंबर की पार्टी बनाकर रह गई थी। गठबंधन करके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी-दोनों ने उम्मीद लगा रखी है कि दो आम चुनावों से जारी दिल्ली में उनका सूझा शायद कम हो जाए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले तक ऐसा नहीं लग रहा था कि विगत के दो चुनावों से इतर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इतिहास इस बार उलट होने जा रहा है। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दोनों पार्टियों को सहानुभूति लहर उठने की उम्मीद है। उन्हें लाता है कि सहानुभूति की लहर से इस बार भारतीय जनता पार्टी के किले में पतल सकता है।

शराब घोटाले में केजरीवाल के पहले उनके दो स्तंभों पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी जमानत की याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। इसी शराब नीति घोटाले में दिल्ली

से तीसरी बड़ी गिरफ्तारी केजरीवाल की हुई है। इसी केस में भारत राष्ट्र समिति की नेता और पार्टी अध्यक्ष के. चंदेश्वर राव की बेटी के कविता भी गिरफ्तार है। केजरीवाल की गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने नौ बार समन देकर उन्हें बुलाया। लेकिन हर बार वे ईडी के सामने जाने से बचते रहे। केजरीवाल का राजनीतिक अनुभव भले ही कम हो, लेकिन उनकी पैतृबलीजी से भाव है कि राजनीति करने में वे पुराने से पुराने नेताओं पर भारी हैं। समन को अनदेखा करके एक तरह से वे इस मुद्दे को खिंचा रखे और इसके जरिए अपने लिए वोटर्स की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते रहे। गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ना देकर भी केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं। ईडी की हिरासत से ही वे दिल्ली के लिए दो आदेश जारी कर चुके हैं। पहले में जहां उन्होंने दिल्ली की सीवर व्यवस्था सुधार करने का आदेश दिया है, वहीं उनका दूसरा आदेश स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त रखना है। दिल्ली में विपक्षी भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी इस पर हंगामा कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से आम केजरीवाल को हटाने की मांग वाली

याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई। जिसे हाईकोर्ट ठुकरा चुका है। इसके बावजूद नैतिकता के आधार पर भाजपा केजरीवाल से इस्तीफा की मांग कर रही है। लेकिन केजरीवाल के खेमे के तर्क हैं कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपने पद से इस्तीफा दे ही देना होगा। इस तर्क के सहारे केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर जमे हुए हैं। हिरासत से आदेश देना और उसका आम आदमी पार्टी द्वारा भरपूर प्रचार किया जाना दरअसल केजरीवाल के प्रति सहानुभूति हासिल करने की प्रक्रिया का ही विस्तार है। भारतीय समाज मनुक होता है। इस मनुकता का फायदा हर राजनीतिक दल अपने तर्क उठाते रहे हैं। इसी अंदाज में केजरीवाल परिवार भी आगे बढ़ रहा है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के भावुकताभरे बयान भी इसका ही उदाहरण हैं। दरअसल इन कदमों में आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जेल में रहते हुए भी आम आदमी पार्टी प्रमुख सिर्फ दिल्ली के ही बारे में सोच रहे हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की कोशिश इस बहाने

सहानुभूति हासिल करना है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के एक बयान से दिल्ली सरकार की बर्खास्तगी को लेकर अटकलें तेज हो गईं। उपराज्यपाल ने यह कह दिया कि जेल से दिल्ली की सरकार नहीं चलने दी जाएगी। उपराज्यपाल के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिशों का जोरदार विरोध किया। वैसे माना जा रहा है कि यह विरोध भी आम आदमी पार्टी की रणनीति का ही हिस्सा है। ताकि कई सरकार दिल्ली सरकार को बर्खास्त कर दे। इससे केजरीवाल के पक्ष में जोरदार लहर उठ खड़ी होगी और मौजूदा आम चुनावों में आम आदमी पार्टी इसका फायदा उठा सकेगी।

वैसे भारतीय जनता पार्टी के बारे से केजरीवाल को दोषी बनाने की खूब कोशिशों हो रही हैं। दिल्ली में विपक्षी दल होने के नाते उसकी यह जिम्मेदारी भी है। लेकिन यह भी सच है कि दिल्ली बीजेपी की यह कोशिश बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है। दिल्ली का एक वर्ग ऐसा भी है, जो मानता है कि केजरीवाल को तंग किया जा रहा है। दिल्ली की बसों, मेट्रो आदि में ऐसी चक्कर चुनाई दे रही हैं। हालांकि एक तबका ऐसा भी है, जो मानता है कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से पहले केजरीवाल की भ्रष्ट कोशिशें रूखने वाले में उस वर्ग के लोग ज्यादा हैं, जिन्हें दिल्ली सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। हालांकि दिल्ली की खस्ताहाल बसें, व्यवस्था की दिशाई आदि के चलते केजरीवाल सरकार से नाराजगी रखने वाला भी एक वर्ग है। जो इस गिरफ्तारी को जायज उहारा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को जानाबूत बयानों में मुद्दी कोशिश की खिंचा सच-छद्मदर है, जैसी हो गई है। लोग घुटकियां देने से बाज नहीं रहे हैं। लोगों का आम कहना है कि जिस कांग्रेस को

# कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खतरे और नियंत्रण



## -दिनेश सी शर्मा-

गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट जैनीमो को लेकर मचे हवा-हल्ले ने इस तकनीक, इसके संवेधित नियामक तंत्र और सरकार की भूमिका को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों को अलग ध्यान खींचा है। एक व्यक्ति द्वारा इन चैटबॉट से प्रशान्तमंथी और फासिवाह को लेकर कुछ सवाल का उत्तर शेरार करके के बाद सोशल मीडिया पर खासै दुस्त बहाना का विषय बने हुए हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने तुलत-कुलत कहा कि प्रशान्तमंथी पर विचार रूप से पूछे गए सवाल का जवाब फ़ायदापूर्ण है और यह आईटी क्षेत्र पर अन्य कानूनों के त्नातिक गैर-जानूनी सामग्री को, माध्यम वने व्यक्तियों या प्लेटफॉर्मस द्वारा शेरार करना, नियमों प्राक्कानों का उल्लंघन है। मंत्री के इस उत्तर के बाद मालाया का परामर्श प्रभव जारी हुआ, जिसमें मालाया या गिफ्ट उपभोग का को अंडर-रेटिंग या गैर-मरोसेमंनो एआई मॉडलस एवं सॉफ्टवेयरस मुबिया करवाने से पूर्व भारत सरकार ने विवेच्य अनुमति लेना जरूरी होगा।



भारत में एआई और अन्य नवीनतम तकनीकों को लेकर नियामक तंत्र और व्यवस्था की अपरुपस्थिति में पहले मंत्री की प्रतिक्रिया और फिर परामर्श प्रभव जारी करने वाले उभय को अहिक ढक से अहिक, समस्या बनने पर आनन-फ़ानन में किया जुगाड़कर कहा जा सकता है। नई-नई तकनीक से बनने वाली नवीन स्थितियों से निपटने को लेकर सरकारों का इतिहास खराब रहा है। तकरीबन आधा सदी पहले तकनीक विकास महानिदेशालय बनाया गया था। इसमें विदेशी तकनीकों की आधार पर एक अति शकंकर चौकीदार की भूमिका निभाई। यह विभाग 1960 के दशक में अमेरिकी कोर्पोरेशनों द्वारा भारत में इंटरनेटिकी का उपलव्ध गुरु बनने संबंधी अनुमृतियों को खारिज करने के लिए उत्तरदायी है। जब 1980 के दशक में टेल्साल इंस्ट्रूमेंट

नामक कंपनी ने बंगलोर से सेटलैटइडरस के जरिये सॉफ्टवेयर निर्यात करना शुरू किया (उस तक यह एवकम नई चीज थी) तब भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कहां कि जो कुछ भी भेजा जाए, उसका प्रिंटआउट जमा करवाया जाए, इस आधार पर कि कहीं राष्ट्र से संवेधित मुद्र सूचनाएं तो नहीं प्रेषित हो रही। प्रसुतर में जो मिले, वह था ओ और 1 के रूप में बान्दनीयता के तरे कगारों का खतना बड़ा देर, जिससे कारगार भर जाएं एवं 1990 के दशक में, उद्योग मंत्रालय के एक बान्द ने बेवसीत बनाने वाली एक कंपनी द्वारा लुडइस के अर्जी मरीठी उद्योगीनिश विभाग को विचारार्थ हस्तांतरित कर दी, क्योंकि उद्योग विधि में जेनेरेटिव इंजीनियरिंग प्रकृति किए जाने का जिक्र था। हमारी बाइराही की कार्यशैली को देखते हुए, कोई भी समझ सकता है कि गूगल, मेटा, एपल या ऑनप एआई का मीडिया क्या होगा, जब वे अनुमति पत्र में अपने खासै एलॉरिदम का प्रिंटआउट खासै तंत्रकानों में बंदे बाइकों को सौंपेंगे।

एआई और मंत्रालय एक ककरतरफा चलताक नीतिगत परामर्श प्रभव जारी करने की बजाय, निर्यात और निर्यात संवेधित बताने के विशय में निर्यात संवेधित बताने को शांतिन करना जरूरी है। एआई पर विचार अब तक सिर्फ इस्को बरवते रखने या सारथय्य या नान्मयेक एवं स्टार्टअप की तरक्की तक सीमित रहा है। उसर कर्मियों जितनी जल्दी हो सके, बाजार में उप-नए की जरूरत उतारना या फिर मौजूद बाजार में नए कर्मियों खानना बचाती हैं। यदि उपभोगका एक पैसा मंडल बनने मिले, जिसमें इमेज रिक्ोगनिशन सॉफ्टवेयर हो, तो जाहिर है सेवा संबंधी शर्तों को पढ़ने की जखमत उठाना होगा इस्तेमाल करने को उलपला रहेगा। तकनीक इंजाय करवने वाली कर्मियोंको को शिकायत है कि अतिशायी नियामक नियंत्रण उनके

# चुनौती बनता मानसिक अवसाद



## -सीमा अग्रवाल-

विषय स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी न होना और शारीरिक रहसत से नहीं होना बल्कि स्वास्थ्य सामाजिक, मानसिक और शारीरिक तीनों से जुड़ा है। इन तीनों में जहां भी व्यक्ति कमजोर है वहां वह अस्वस्थ माना जाता है, उसे सेहतमंद नहीं कहा सकते। अच्छी सेहत वाला व्यक्ति वह है जो इन सभी मानकों पर बहुत ही अच्छे स्तर पर अपनी जिम्मेदारियों बसवूदी निभा रहा है। जो जीवन में सकारात्मक माना जाय और किसी भी सूरत में अनुमति नहीं मिलेगी। इस वर्ग में, लोगों को बेक-व्यवहार को बदलने वाली या विशेष जोखिमदात समूह सामाजिक नियंत्रण (आचार-व्यवहार अथवा आर्थिक साम्योदिक पहचान और मानकों का वर्गीकरण करना, वास्तविक समय में या फिर पूर्व बंदक बामोदिक प्रणाली जैसे कि फेसियल रिक्ोगनिशन इत्यादि जैसे एप्लिकेशंस का उपयोग शामिल है) मौजूदा लोअर्थी साम्य उपयोगों में अथवा ऐरिसेडिव एप्लिकेशंस जैसे कि चैटजीपीटी को भी पारदर्शिता आवश्यकताओं पर सखर उतरना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि इससे गैर-कानूनी सामग्री और कॉपीराइट प्राय डाटा प्रकाशित न होने पाय। सीमित जोखिम वर्ग की एआई प्रकृति को जमानत के भी अखंडक नरम, किंतु पारदर्शी नियमों का पालन करना होगा। एआई को लेकर भारत को तीन चीजें करने की जरूरत है। प्रथम, एक डुस्त नीति और नियामक तंत्र को बान्दना, जिसका ध्यान न केवल सारथय्य संबंधी जोखिमों में भी केंद्रित हो। इसके लिए सभी संवेधित बताने, मसलन, कर्मियों इंजाय करवने वाली कर्मियों, समाज शास्त्री, स्थिति संबंधी, सायटी, डॉक्टर और नीति-निर्माताओं की सलाह को सुने और पारदर्शी ढंग से शांतिन किया जाना जरूरी है।

मानवाधिकार है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता। गौरवला है कि मेटा लक्ष्य सच अनुवांशिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक हर तरह की हो सकती है। इस अवस्था से किसी इंसान को बाहर निकालना, आर्थिक और शारीरिक तीनों से जुड़ा है। इन तीनों में जहां भी व्यक्ति कमजोर है वहां वह अस्वस्थ माना जाता है, उसे सेहतमंद नहीं कहा सकते। अच्छी सेहत वाला व्यक्ति वह है जो इन सभी मानकों पर बहुत ही अच्छे स्तर पर अपनी जिम्मेदारियों बसवूदी निभा रहा है। जो जीवन में सकारात्मक माना जाय और किसी भी सूरत में अनुमति नहीं मिलेगी। इस वर्ग में, लोगों को बेक-व्यवहार को बदलने वाली या विशेष जोखिमदात समूह सामाजिक नियंत्रण (आचार-व्यवहार अथवा आर्थिक साम्योदिक पहचान और मानकों का वर्गीकरण करना, वास्तविक समय में या फिर पूर्व बंदक बामोदिक प्रणाली जैसे कि फेसियल रिक्ोगनिशन इत्यादि जैसे एप्लिकेशंस का उपयोग शामिल है) मौजूदा लोअर्थी साम्य उपयोगों में अथवा ऐरिसेडिव एप्लिकेशंस जैसे कि चैटजीपीटी को भी पारदर्शिता आवश्यकताओं पर सखर उतरना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि इससे गैर-कानूनी सामग्री और कॉपीराइट प्राय डाटा प्रकाशित न होने पाय। सीमित जोखिम वर्ग की एआई प्रकृति को जमानत के भी अखंडक नरम, किंतु पारदर्शी नियमों का पालन करना होगा। एआई को लेकर भारत को तीन चीजें करने की जरूरत है। प्रथम, एक डुस्त नीति और नियामक तंत्र को बान्दना, जिसका ध्यान न केवल सारथय्य संबंधी जोखिमों में भी केंद्रित हो। इसके लिए सभी संवेधित बताने, मसलन, कर्मियों इंजाय करवने वाली कर्मियों, समाज शास्त्री, स्थिति संबंधी, सायटी, डॉक्टर और नीति-निर्माताओं की सलाह को सुने और पारदर्शी ढंग से शांतिन किया जाना जरूरी है।

उत्पद्यु.एच.ओ. ने 2013 में मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य के पारपर मल्टव देते हुए वर्डव हेल्थ रिसैरचों में एक व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्ययोजना को मंजूरी दी थी। जो 2013-2020 तक के लिये थी। इस कार्ययोजना में सेहत रेशों ने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की करम खासै थी। भारत ने भी इस कार्ययोजना को अपने यहां लागू किया था।

एआई को लेकर एक ककरतरफा चलताक नीतिगत परामर्श प्रभव जारी करने की बजाय, निर्यात और निर्यात संवेधित बताने के विशय में निर्यात संवेधित बताने को शांतिन करना जरूरी है। एआई पर विचार अब तक सिर्फ इस्को बरवते रखने या सारथय्य या नान्मयेक एवं स्टार्टअप की तरक्की तक सीमित रहा है। उसर कर्मियों जितनी जल्दी हो सके, बाजार में उप-नए की जरूरत उतारना या फिर मौजूद बाजार में नए कर्मियों खानना बचाती हैं। यदि उपभोगका एक पैसा मंडल बनने मिले, जिसमें इमेज रिक्ोगनिशन सॉफ्टवेयर हो, तो जाहिर है सेवा संबंधी शर्तों को पढ़ने की जखमत उठाना होगा इस्तेमाल करने को उलपला रहेगा। तकनीक इंजाय करवने वाली कर्मियोंको को शिकायत है कि अतिशायी नियामक नियंत्रण उनके

एआई और मंत्रालय एक ककरतरफा चलताक नीतिगत परामर्श प्रभव जारी करने की बजाय, निर्यात और निर्यात संवेधित बताने के विशय में निर्यात संवेधित बताने को शांतिन करना जरूरी है। एआई पर विचार अब तक सिर्फ इस्को बरवते रखने या सारथय्य या नान्मयेक एवं स्टार्टअप की तरक्की तक सीमित रहा है। उसर कर्मियों जितनी जल्दी हो सके, बाजार में उप-नए की जरूरत उतारना या फिर मौजूद बाजार में नए कर्मियों खानना बचाती हैं। यदि उपभोगका एक पैसा मंडल बनने मिले, जिसमें इमेज रिक्ोगनिशन सॉफ्टवेयर हो, तो जाहिर है सेवा संबंधी शर्तों को पढ़ने की जखमत उठाना होगा इस्तेमाल करने को उलपला रहेगा। तकनीक इंजाय करवने वाली कर्मियोंको को शिकायत है कि अतिशायी नियामक नियंत्रण उनके

एआई और मंत्रालय एक ककरतरफा चलताक नीतिगत परामर्श प्रभव जारी करने की बजाय, निर्यात और निर्यात संवेधित बताने के विशय में निर्यात संवेधित बताने को शांतिन करना जरूरी है। एआई पर विचार अब तक सिर्फ इस्को बरवते रखने या सारथय्य या नान्मयेक एवं स्टार्टअप की तरक्की तक सीमित रहा है। उसर कर्मियों जितनी जल्दी हो सके, बाजार में उप-नए की जरूरत उतारना या फिर मौजूद बाजार में नए कर्मियों खानना बचाती हैं। यदि उपभोगका एक पैसा मंडल बनने मिले, जिसमें इमेज रिक्ोगनिशन सॉफ्टवेयर हो, तो जाहिर है सेवा संबंधी शर्तों को पढ़ने की जखमत उठाना होगा इस्तेमाल करने को उलपला रहेगा। तकनीक इंजाय करवने वाली कर्मियोंको को शिकायत है कि अतिशायी नियामक नियंत्रण उनके

एआई और मंत्रालय एक ककरतरफा चलताक नीतिगत परामर्श प्रभव जारी करने की बजाय, निर्यात और निर्यात संवेधित बताने के विशय में निर्यात संवेधित बताने को शांतिन करना जरूरी है। एआई पर विचार अब तक सिर्फ इस्को बरवते रखने या सारथय्य या नान्मयेक एवं स्टार्टअप की तरक्की तक सीमित रहा है। उसर कर्मियों जितनी जल्दी हो सके, बाजार में उप-नए की जरूरत उतारना या फिर मौजूद बाजार में नए कर्मियों खानना बचाती हैं। यदि उपभोगका एक पैसा मंडल बनने मिले, जिसमें इमेज रिक्ोगनिशन सॉफ्टवेयर हो, तो जाहिर है सेवा संबंधी शर्तों को पढ़ने की जखमत उठाना होगा इस्तेमाल करने को उलपला रहेगा। तकनीक इंजाय करवने वाली कर्मियोंको को शिकायत है कि अतिशायी नियामक नियंत्रण उनके







